राष्ट्रीय सहारा, वाराणसी

दिनांक: 17.10.2020

डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

वाराणसी(एसएनबी)। भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ ने भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित चेतावनी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को डीरेका गुमटी मार्केट में आम सभा कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष राधा बल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में एक भी सरकारी उद्योग को स्थापित नहीं किया, जो सरकारी उद्योग है उसे समाप्त करने का जो षड्यंत्र कर रही है वह न तो देश के हित में है और न ही आम जनता के हित में।

वीडी दुबे ने कहा कि भारत सरकार ने रेल में ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देकर देश के आम आदमी के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का जो कुचक्र रच रही है। राकेश पांडेय ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार को रोजगार सृजन करने की एक निति बनानी चाहिए। वक्ताओं ने मांगों को भी उठाया। संचालन कृष्ण मोहन तिवारी, अध्यक्षता संगठन केसी पांडेय ने किया। सभा में देवतानंद, राकेश कुमार, प्रदीप कुमार यादव, सुशील सिंह, राजेन्द्र पाल, रोहित शर्मा, अश्वनी यादव, श्याम मोहन उपाध्यक्ष, राहुल पांडेय, राम सिंह, गौरव श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सिंह, सुकेश सिन्हा, अमित सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, संदीप आर्य, रंग बहादुर यादव, विनोद कुमार सिंह, अश्वनी सिंह, पवन कुमार राय, दीपेश, प्रमोद कुमार राय, जय प्रकाश, सुरेश सिन्हा, अरविंद, अखिलेश राय, धीरेंद्र सिंह, अनुराग, अक्षय, सुमीत अग्रहरी आदि लोग मौजूद रहे।

आज, वाराणसी

दिनांक: 17.10.2020

सरकार मजदूर विरोधी नीति वापस ले वर्ना छेड़ेंगे बड़ा आन्दोलन

चेतावनी सप्ताहके अन्तिम दिन डीएलडब्ल्यू मजदूर संघकी हुंकार

चेतावनी सप्ताहके अन्तिम दिन डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ सरकारपर जमकर हमला किया। कहा मौजूदा केन्द्र सरकार देशमें एक भी उद्योग स्थापित करनेमें नाकाम रही। इसके उलट स्थापित उद्योगों और उपक्रमोंको ही समाप्त करने षडयंत्रमें जुट गयी। संघने चेताया कि यदि सरकार मजदूर विरोधी नीतियोंका वापस नहीं लेती तो वे सड़कपर उतर कर बड़ा आन्दोलन करनेको बाध्य होंगे। भारतीय मजदूर संघके आह्वानपर चले इस चेतावनी सप्ताहके अन्तिम दिन शुक्रवारको डीरेका परिसर स्थित गुमटी मार्केटमें आम सभाका आयोजन किया गया। सभाको सम्बोधित करते हुए संघके कार्यवाहक अध्यक्ष राधावल्लभ त्रिपाठीने कहाकि सरकारी उद्योगोंको निजी हाथोंमें सौंपनेकी सरकार की नीति न तो देश हितमें है और न ही आमजन के हितमें है। इससे देशमें बेरोजगारी भी बढ़ेगी। डीरेका कर्मचारी परिषद सदस्य वीडी दुबेने कहाकि भारत सरकारका ट्रेनोंको निजी क्षेत्रमें

देनेका फैसला आम आदमीपर आर्थिक बोझ बढ़ानेका उपक्रम ही कहा जा सकता है। जिला मंत्री राकेश पाण्डेयने कहाकि सरकार को रोजगार सृजन की नीति बनानी चाहिए मगर वह स्थापित उद्योगको समाप्त कर बेरोजगारी बढ़ानेके कार्योंमें ही लिप्त है। अन्य वक्ताओंने रेलके निगमीकरण, निजीकरणके प्रस्तावको वापस लेने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, मजदूर विरोधी श्रम कानूनको वापस करने, बोनस देने तथा एक्ट अप्रेन्टिसोंके समायोजनकी मांग की। सभामें मौजूद संघके पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओंने एकसुरमें कहा यदि डीरेकाका निगमीकरण किया गया तो सरकारको इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। संचालन महामंत्री कृष्णमोहन तिवारी एवं अध्यक्षता संघटन मंत्री के.सी. पाण्डेयने की। सभामें सर्वश्री देवतानंद, राकेश कुमार, कर्मचारी परिषद सदस्य प्रदीप कुमार यादव, सुशील सिंह, राजेन्द्र पाल, रोहित शर्मा, अश्वनी यादव, श्याम मोहन उपाध्यक्ष, राहुल पांडेय, राम सिंह, गौरव श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सिंह, सुकेश सिन्हा, अमित सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, संदीप आर्य, रंग बहादुर यादव, विनोद कुमार सिंह, अश्वनी सिंह, पवन कुमार राय, दीपेश, प्रमोद कुमार राय, जय प्रकाश, सुरेश सिन्हा, अरविंद, अखिलेश राय, धीरेंद्र सिंह, अनुराग, अक्षय, सुमीत अग्रहरी आदि लोग उपस्थित रहे।